श्रीमती राम सखी देवी

बनाम

छत्रा देवी और अन्य

12 जुलाई, 2005

[माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिजीत पसायत और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच. कपाड़िया]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 100-द्वितीय अपील-उच्च न्यायालय का निर्णय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना-निर्धारित, स्थायी नहीं।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में दिया गया निर्णय, धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना, स्थायी है।

मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया:

दंड प्रक्रिया संहितां की धारा 100 की उपधारा (3) के अनुसार, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल विधि के संतोषजनक प्रश्न या प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जहाँ उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि किसी भी मामले में कोई संतोषजनक विधि प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को उपधारा (4) के अंतर्गत तैयार करेगा और दूसरी अपील की सुनवाई धारा 100 की उपधारा (5) में बताए अनुसार तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यह नहीं दर्शाता कि कोई भी महत्वपूर्ण विधि प्रश्न तैयार किया गया है या यदि कोई प्रश्न तैयार किया गया है, तो उस पर दूसरी अपील की सुनवाई की गई है। ऐसी स्थिति में, निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

[545-एच; 546-ए, जी]।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, **[2000] 1 एससीसी 434***; रूप सिंह(मृत) एलआर के माध्यम से. वी. राम सिंह (मृत) एलआर के माध्यम से,* **[2000] 3 एससीसी 708***; कन्हैयालाल एवं अन्य। वी. अनुपकुमार और अन्य,* **जेटी (2002) 10 एससी 98***; आर. लक्ष्मी नारायण बनाम शांति, [2001) 4 एससीसी 688; एम.एस.वी राजा और अन्य. वी. सीनी थेवर और अन्य,* **[2001] 6 एससीसी 652***; आर. वी.ई. वेंकटचला गौंडर बनाम अरुल्मिगु जी विश्वेसरास्वामी और वी.पी. टेम्पल एंड अन्य,* **[2003] 8 एससीसी 752***; मोहम्मद मोहम्मद एलआरएस द्वारा अली (मृत) वी. जगदीश कलिता और अन्य,* **[2004] 1 एससीसी 271***; चडत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य:,* **जेटी [2004] 6 एससी 296***; किशोरी लाल और अन्य. वी मदन गोपाल (डी) एलआरएस द्वारा और अन्य,* **जेटी (2004) 8 एससी 422 और** *माथाकला कृष्णैया बनाम वी राजगोपाल,* **[2004] 10 एससीसी 676***, पर अवलंबन किया गया।*

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2005 की दीवानी अपील संख्या 3608 ।

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2002 के निर्णय एवं आदेश से 1998 की एस.ए. संख्या 244 में।

अपीलकर्ता की ओर से डी.के. ठाकुर और देबाशीष मिश्रा।

उत्तरदाताओं की ओर से कृष्ण प्रसाद, संजय आर. हेगड़े, एस.के. वर्मा और एन.एस. बिष्ट।

न्यायालय का निर्णय **अरिजीत पसायत**, **न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया। अनुमति प्रदान की गई।

अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के तहत द्वितीय अपील में दिए गए निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाया है। उत्तरदाता मूल वादी - इश्राज नारायण सिंह

के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। मूल वादी ने भूमि पर अपने स्वामित्व की घोषणा और अपीलकर्ता श्रीमती राम सखी देवी, जो इस मुकदमे में उत्तरदाता संख्या 3 हैं, के स्वामित्व के अभाव की घोषणा हेतु एक वाद दायर किया है। विचारण न्यायालय ने इस मुकदमे में फैसला सुनाया था लेकिन अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे उलट दिया। उत्तरदाताओं ने पटना उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की। इस आक्षेपित फैसले के तहत उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को बहाल कर दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को अपास्त कर दिया।

यद्यपि अपील के समर्थन में कई बिंदुओं पर जोर दिया गया था, लेकिन मुख्य दलील यह थी कि उच्च न्यायालय संहिता की धारा 100 के अनुसार विधि का कोई संतोषजनक प्रश्न तैयार किए बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय संहिता की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल द्वितीय अपील में अपील स्वीकार करते समय तैयार किए गए विधि के संतोषजनक प्रश्न के आधार पर ही कर सकता है। द्वितीय अपील की सुनवाई और निर्णय केवल विधि के संतोषजनक प्रश्न, यदि कोई हो, के आधार पर ही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विधि में टिकने योग्य नहीं है।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि कानून का प्रश्न स्वयंसिद्ध है और इस तकनीकी दलील पर कि कानून का प्रश्न तैयार नहीं किया गया है, इस तर्कसंगत निर्णय को अपास्त नहीं किया जाना चाहिए।

संहिता की धारा 100 की उपधारा 3 के अनुसार, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल विधि के संतोषजनक प्रश्न या प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। जहाँ उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में विधि का कोई संतोषजनक प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को उपधारा 4 के अंतर्गत स्थापित करेगा और

धारा 100 की उपधारा 5 में बताए अनुसार तैयार किए गए प्रश्न पर दूसरी अपील की सुनवाई की जाएगी।

संहिता की धारा 100 "धारा अपील" से संबंधित है। यह प्रावधान इस प्रकार है:

"धारा 100 - (1) इस संहिता के मूल में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई संतोषजनक प्रश्न अंतर्ग्रस्त है।"

(2) इस धारा के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित अपीलीय डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अंतर्गत अपील में, अपील ज्ञापन में उस अपील में शामिल विधि के मूल प्रश्न का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का कोई संतोषजनक प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो वह उस प्रश्न का निरूपण करेगा।

(5) अपील की सुनवाई इस प्रकार प्रस्तुत प्रश्न पर की जाएगी और उत्तरदाता को अपील की सुनवाई के समय यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है:

बशर्ते कि इस उपधारा की कोई भी बात न्यायालय की किसी अन्य संतोषजनक विधि प्रश्न पर अपील, जो उसके द्वारा नहीं बनाई गई है, सुनवाई करने की शक्ति को, कारणों को दर्ज करके, छीनने या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है।"

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह पता नहीं चलता कि कोई भी महत्वपूर्ण विधि प्रश्न तैयार किया गया है या यदि कोई प्रश्न तैयार किया गया है, तो उस पर दूसरी अपील की सुनवाई की गई है। ऐसा होने पर, निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, [2000] 1 एससीसी 434 में इस न्यायालय ने कंडिका 10 में इस प्रकार कहा है:

> "10. अब धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, 1976 के संशोधन के बाद, उच्च न्यायालय के लिए कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है और ऐसा किए बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को पलटना स्वीकार्य नहीं है।"

रूप सिंह (मृत) बनाम *राम सिंह (मृत)* एलआरएस के माध्यम से, [2000] 3 एससीसी 703, में इस न्यायालय ने यह अभिव्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित अपीलों तक ही सीमित है। उक्त निर्णय के कंडिका 7 में लिखा है:

> "7. यह दोहराया जाना चाहिए कि धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय का द्वितीय अपील पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिनमें विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो और यह उच्च न्यायालय को शुद्ध तथ्यों के प्रश्नों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है जबकि वह धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए शुद्ध तथ्यों के प्रश्नों में हस्तक्षेप करता है। इसके अलावा, मामले का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील स्वीकार करते समय अपने द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रश्न पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि आलोचना किए गए निर्णय में इसका

कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, तथ्यान्वेषी न्यायालयों ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह माना कि उत्तरदाता ने परिसर का कब्जा बटाई के रूप में, अर्थात् किरायेदार के रूप में लिया था और उसका कब्जा अनुज्ञेय था और इस बात का कोई तर्क या प्रमाण नहीं था कि यह कब प्रतिकूल और विरोधी हो गया। नीचे दी गई दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्ष्य और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित थे और उन निष्कर्षों में कोई विकृतियाँ, अवैधता या अनियमितता नहीं थी। यदि उत्तरदाता ने पट्टेदार के रूप में या बटाई समझौते के तहत वाद भूमि का कब्ज़ा प्राप्त किया है, तो अनुमेय कब्जे से उसे असली मालिक की जानकारी के विपरीत शत्रुतापूर्ण दुश्मनी और कब्ज़ा दर्शाने के लिए ठोस और ठोस सबूतों के द्वारा यह स्थापित करना होगा। केवल लंबे समय तक कब्ज़ा रखने से अनुमेय कब्ज़ा प्रतिकूल कब्ज़े *ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार*, [1994] 6 एससीसी 591 में परिवर्तित नहीं हो जाता । इसलिए उच्च न्यायालय को दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।"

कन्हाल्यालालंद अन्य बनाम अनूपकुमार एवं अन्य, संयुक्त न्यायाधिकरण (2002) 10 एससी 98 में भी यही स्थिति दोहराई गई है।

आर. लक्ष्मी नारायण बनाम संथी, [2001] का भी संदर्भ लिया जा सकता है 4 एससीसी 688, एमएस वी. राजा और अन्य. वी. सीनी थेवर और अन्य, [2001] 6 एससीसी 652, आर. वी.ई. वेंकटचला गौंडर बनाम अरुल्मिगु विश्वेसरस्वामी और वी.पी. मंदिर और अन्य, [2003] 8 एससीसी 752, मोहम्मद अली (मृत) एलआरएस द्वारा वी. जगदीश कलिता और अन्य, (2004) 1 एससीसी 271, चदत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य, जेटी (2004) 6 एससी 296, किशोरी लाल और अन्य वी. मदन गोपाल (डी)

एलआरएस द्वारा और ऑन, जेटी (2004) 8 एससी 422 और मथकला कृष्णैया बनाम वी. राजगोपाल, [2004] 10 एससीसी 676।

इन परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। हम इस मामले को विधि अनुसार निपटान हेतु उच्च न्यायालय को भेजते हैं। अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है, जिसमें लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

डी.जी. अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।